

प्रेषक,

अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायती राज, उ०प्र०।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 07 फरवरी, 2020

विषय: राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में प्राथमिकता निर्धारण के संबंध में।

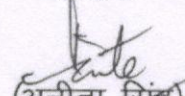
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2630/33-3-2019-एल०सी०/2019 दिनांक-18.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष-2020-21 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के कार्ययोजना की प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है। अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 18.12.2019 में कुछ ऐसे बिन्दु अंकित हो गये हैं, जिनका उल्लेख चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14वें वित्त आयोग की मार्ग-निर्देशिका में नहीं है, जैसे व्यक्तिगत शौचालय आदि।

2- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक-18.12.2019 द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में से उन्ही कार्यो को ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाए, जिनका प्रावधान राज्य वित्त एवं 14वें वित्त आयोग की मार्ग-निर्देशिका में किया गया है।

3- कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 18.12.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

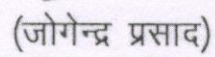

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

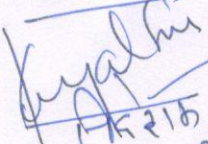
1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ०प्र०।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
3. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

4063

DDCC



07/01/2020

2905 - 8/1/2020

DD (P)

129